हरिभूमि

मध्यांचल भूमि

रायपुर, गुरुवार 4 जून 2026

तापमान

अधिकतम 37.0 डिग्री

न्यूनतम 24.0 डिग्री

11 अंबुजा विद्यापीठ में भारतीय भाषा समर कैंप...

12 सुशासन तिहार में लोगों की समस्याओं का मौक़े पर ...

खबर संक्षेप

4 जुआरी गिरफ्तार, 6 हजार रुपए जब्त

बिलाईगढ़। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले में अवैध जुआ सट्टा के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने के निर्देश किया गया था, जिस पर 3 जून को मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली प्रमोद यादव के नेतृत्व में ग्राम गुडेली में, टोनही तालाब के पास ताश पत्ती से रूपये पैसे का दाव लगा कर जुआ खेल रहे जुआडीयान विश्वकर्मा भास्कर, अवधराम मानिकपुरी, किशोर पटेल और लकेश पटेल के पास एवं फड़ से नगदी 6000 रुपए और 52 पत्ती ताश को जब्त कर धारा 3(2) छ ग जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपीयों क्रो गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई।

भाजपा मंडल सुहेला की बैठक कल मोहरा में

हिरमी रावन। भारतीय जनता पार्टी सुहेला मंडल की बैठक कल 4 जून को सुबह 10:30 बजे को समरसता भवन मोहरा में विजय केशरवानी के मुख्य आतिथ्य एवं हेमन्त बघमार की अध्यक्षता मे आयोजित की गई है। इसमें भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अदिति बघमार जनपद अध्यक्ष डॉ. दौलत पाल, जिला पंचायत सदस्य डॉ. मोहन वर्मा, जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव, विधायक प्रतिनिधि करण वर्मा शामिल होंगे। भाजपा मंडल महामंत्री संतन बांधे, युगल किशोर वर्मा, रामकुमार साहू ने सभी पदाधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आग्रह किया है।

अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए रायपुर में 5 जून को रोजगार मेला

बिलाईगढ़। अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए रोजगार हेतु रोजगार मेला का आयोजन 5 जून को प्रातः 11 से 3 बजे तक शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में किया जा रहा है। यंग इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस रोजगार मेला में क्रेडालिस केपिटल प्रा. लिमिटेड आई ट्रेड टेलिमेटिक्स निगरानी, जीपीएस, रामा उद्योग प्रा. लिमिटेड, बारबर्रिक ट्रांसफार्मर्स, अविनाश डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड एवं स्काई ऑटोमोबाइल (मारूति नेक्सा), रायपुर द्वारा योग्यतानुसार अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित आवेदकों को उनके योग्यता एवं पद के अनुसार लगभग 11 हजार रुपये ते 30 हजार रुपये तक मासिक वेतन प्रदान किया जायेगा तथा जिला रायपुर उनका कार्यक्षेत्र रहेगा। छत्तीसगढ़ के समस्त इच्छुक अस्थिबाधित दिव्यांगजन जो बिना व्हीलचेयर के चलने फिरने में सक्षम है तथा जिनकी आयुसीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, वे इस रोजगार मेला में सम्मिलित हो सकते है। दिव्यांगजन अपने सभी प्रमाण-पत्रों जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक/, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, बीई, आईटीआई,/डीसीए, पीजीडीसीए आदि उत्तीर्ण की अंकसूची, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि के मूल एवं फोटोकॉपी की एक प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ कैम्प में उपस्थित हो सकते है। आवेदकों को रोजगार मेला में जाने जाने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। खाने-पीने एवं ठहरने की व्यवस्था स्वयं आवेदक को करनी होगी।

नपा टीम ने सड़क किनारे लगने वाले ठेले खोमचे सहित होर्डिंग्स हटवाने किया मार्किंग

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सिमगा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशिभूषण श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी धीरेन्द्र दुबे की संयुक्त टीम ने बुधवार को नगर पालिका सिमगा में शहर के अंदर मुख्य सड़क के किनारे व नगर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक में लगने वाले ठेलों खोमचों एवं दुकानों के बोर्ड होडिंग हटवाने सड़क के दोनों ओर चूने से मार्किंग करते हुए समझाईश दी। दुकानदार अपने बोर्ड होर्डिंग टीन शेड को हटा लें तथा ठेला खोमचे वालों को भी सड़क किनारे दुकान नहीं लगाने चेताया गया, अन्यथा नगर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त कवायद

ठेलों खोमचों एवं बोर्ड होडिंग लगाने वाले दुकानदारों को थमाया नोटिस

इस घटनाक्रम का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद घटना के दूसरे ही दिन नगरपालिका अधिकारी ने ठेलों खोमचों एवं बोर्ड होडिंग लगाने वाले दुकानदारों को नोटिस थमाया एवं तीसरे दिन नगरपालिका एवं थाना के संयुक्त टीम ने चेतावनी देते हुए सड़क के दोनों ओर मार्किंग कराया है। साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि अपने अपने ठेलों खोमचों एवं बोर्ड होडिंग आदि को मार्किंग के अंदर कर लेवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बस संचालकों की बैठक बुलाकर उन्हें समझाइश दी जाएगी कि नगर में बस स्टैंड में ही बस खड़ी करें यहां वहां खड़ी करने पर चलानीं कार्रवाई की जायेगी।

गौरतलब हो कि नगर के मुख्य मार्ग में ठेले खोमचों वालों एवं दुकानों के बाहर टीन शेड सामान बोर्ड होर्डिंग लगाने के कारण सड़क बहुत ही सकरा हो जाता है।

जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। मार्ग में भारी वाहनों जैसे रेत से भरी ट्रक, हाईवा एवं बड़ी बड़ी यात्री बसे बेखौफ दौड़ती रहती है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंकाएं बनी रहती है। बता दें कि दो पूर्व ही नगर के जय स्तंभ चौक पर एक दुकान के सामने दस चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर विद्युत खंभा एवं सांकेतिक बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई।

15 जून तक चलेगा अंतर-परिक्षेत्रीय संयुक्त निरीक्षण और निगरानी अभियान

वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने विशेष एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश अनुसार बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण की पहचान, रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से 1 जून से विशेष "एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव" संचालित किया जा रहा है। 15 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वनमण्डल स्तर पर अंतर-परिक्षेत्रीय संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया है जो विभिन्न वन परिक्षेत्रों में भ्रमण कर वन भूमि की स्थिति का परीक्षण करेंगे। अभियान के दौरान गठित निरीक्षण दल वन सीमाओं, वनखण्डों एवं बीट क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करेंगे तथा विशेष रूप से उन कक्षों एवं क्षेत्रों का परीक्षण किया जाएगा जिनकी सीमाएं ग्रामों अथवा कृषि भूमि से लगी हुई हैं। निरीक्षण के दौरान वन सीमाओं, मुनारों की स्थिति, वन भूमि पर संभावित अतिक्रमण, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

अंतर-परिक्षेत्रीय टीमों द्वारा होगा संयुक्त निरीक्षण-अभियान अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों के अधिकारियों को अन्य परिक्षेत्रों में निरीक्षण हेतु नामित किया गया है, जिससे निष्पक्ष एवं प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित परिक्षेत्रों द्वारा आवश्यक अभिलेख, नक्शे, कक्ष इतिहास एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे तथा बीटवार जानकारी का परीक्षण किया जाएगा।

वन क्षेत्रों की सतत निगरानी

वन क्षेत्रों में मानवीय दबाव एवं अन्य गतिविधियों का होगा आकलन-निरीक्षण के दौरान वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों, पशुओं के दबाव, खरपतवार की स्थिति, वन अधिकार मान्यता पत्रों की स्थिति एवं उनके सत्यापन सहित विभिन्न बिंदुओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही वन सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझावों का संकलन भी किया जाएगा। वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा है कि वन भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के माध्यम से वन क्षेत्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी प्रकार के नवीन अतिक्रमण अथवा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये हैं।

भाटापारा को नहीं मिला स्टॉपेज

तिरुपति रक्सौल के मध्य नई ट्रेन सेवा शुरू

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भाटापारा

जिस तरह देश में सोने-चांदी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही भाटापारा में नहीं रुकने वाली ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है और ये आंकड़ा 50 को पार करते हुए 52 तक जा पहुंचा है। क्षेत्र की जनता को समझ नहीं आ रहा है कि भाटापारा शहर के साथ लगातार हो रहे इस अन्याय को जवाबदार जनप्रतिनिधि कैसे बर्दाश्त कर रहे है। पिछले 7 वर्षों से भाटापारा में किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं मिला है।

- भाटापारा में नान स्टॉप ट्रेनों का आंकड़ा 52 तक पहुंचा

तिरुपति से रक्सौल के मध्य 17433/17434 ट्रेन की सुविधा चालू की गई है, जिसका ठहराव भाटापारा में नहीं दिया गया है। इस ट्रेन के चलने से श्री बालाजी के दर्शन के लिए यह ट्रेन काफी अच्छी और सुविधाजनक है। उक्त ट्रेन का रायपुर रेल डिविजन के इस प्रमुख स्टेशन भाटापारा में स्टॉपेज नहीं दिये जाने से है क्षेत्र की जनता काफी आश्चर्य चकित है, क्योंकि वर्तमान में चल रही एक मात्र बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस रायपुर टिटलागढ़ विशाखापत्तनम मार्ग होकर तिरुपति जाती है, जिसमें काफी समय लगता है और अभी प्रारंभ हुई रक्सौल तिरुपति एक्सप्रेस रायपुर गोंदिया चांदापोर्ट बल्लारशाह के रास्ते तिरुपति जा रही है, जिससे समय की काफी बचत होगी।

तिरुपति जैसे धार्मिक स्थान के लिए प्रारंभ की गई इस ट्रेन सुविधा से धार्मिक नगर भाटापारा के लोग वंचित रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रेलवे के नक्शे में भाटापारा का अपना एक अलग स्थान है जहाँ से यात्री और राजस्व दोनों प्राप्त होता है,ऐसे में भाटापारा की लगातार अनदेखी से क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही ▶▶ शेष पेज 11 पर

नालीनुमा ब्रेकर से बढ़े हादसे, रोज बाइक सवार हो रहे दुर्घटना के शिकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| अर्जुनी

बलौदाबाजार-भाटापारा को जोड़ने वाले प्रमुख सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम अर्जुनी के मिरगी मार्ग मोड़ के पास मुख्य मार्ग पर बनाया गया स्पीड ब्रेकर जर्जर और धस गया है व नालीनुमा का आकार ले लिया है, जो हादसे का मार्ग साबित हो रहा है। इसकी मरम्मत पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे राहगीर आये दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। फल विक्रेता रती राम साहू ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के जगहों का धंस जाने व नालीनुमा मार्ग बन जाने के कारण दो पहिया वाहन के पहिये अनियंत्रित हो जा रहे, जिससे इस मार्ग पर हादसे हो रहे हैं। जर्जर रोड और पर्याप्त यातायात चेतावनी संकेतक बोर्ड नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।

बता दे कि दो स्थानों में मिरगी मोड़, टोनाटार तिग्गडा मोड़ के पास बनाया गया स्पीड ब्रेकर के पास मार्ग नालीनुमा मार्ग में तब्दील हो चुका है एवं यहाँ पर कोई संकेतक बोर्ड भी नहीं लगा है । सोमवार शाम इसी स्थान पर दुर्घटना में बाइक सवार जिसमे युवक-युवती गिर गए, व्यस्ततम मार्ग होने के कारण बड़ी दुर्घटना होने से दोनों बाल-बाल बच गए। इस हादसे में मोटरसाइकिल सड़क पर ही क्षतिग्रस्त अवस्था में बिखर गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल की मदद की। ग्रामीणों ने बताया कि खराब जर्जर सड़क होने के कारण अनजान वाहन चालक अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से नालीनुमा मार्ग की शीघ्र सुधार कराने, सुरक्षा संकेतक बोर्ड लगाने तथा एप्रोच रोड का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है अच्छी व सुगम सड़क नहीं होने के कारण अब तक दर्जनभर हादसे व कइयों ने अपनी जान गंवा चुके हैं।

जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में अटल लैब का उद्घाटन

बिलाईगढ़। जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में अटल लैब का उद्घाटन कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पाण्डेय, विधायक उत्तरी जांगड़े और गणमान्य नागरिक ज्योति पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अतिथियों ने लैब का अवलोकन किया और भगवान श्री गणेश के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर लैब का शुभारम्भ किया गया। इस लैब में 136 प्रकार की जांच निशुल्क होगा। इसके पूर्व जिला चिकित्सालय में 78 प्रकार के जांच निःशुल्क और न्यूनतम दर पर दिया जा रहा था। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ पुष्पेंद्र वैष्णव, सिविल सर्जन डॉ दीपक जायसवाल, पूर्व पार्षद अविनाशपुरी गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में लैब कर्मी, मरीज और परिजन उपस्थित थे।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों व जनकल्याणकारी योजनाओं को कार्यकर्ता पहुंचेंगे प्रत्येक घर तक

हरिभूमि न्यूज ▶▶| कसडोल

भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत /"बढ़ता भारत - बदलता भारत/" विषय पर सम्पन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत एवं प्रस्तावना के साथ हुआ। जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉ. सुदीप मानिकपुरी ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत ▶▶ शेष पेज 11 पर

कार्यकर्ताओं ने पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का लिया संकल्प

कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन की आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उक्त बैठक में मंडल पदाधिकारी, मोर्चा-प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

समय सीमा में काम नहीं हुआ या परेशानी आ रही तो कर सकेंगे 1076 में शिकायत

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का जल्द होगा शुभारंभ, अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप लोगों की शिकायत व समस्या का त्वरित रूप से निराकरण कर राहत पहुंचाने के लिए 1076 सीएम हेल्पलाइन प्रारम्भ की जा रही हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के लिए वीडियो कांफ्रेंस से सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन त्वरित शिकायत निवारण हेतु एकीकृत मंच है तथा यह गुड गवर्नेंस की दिशा में राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से नागरिकों की शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली पाँच प्रमुख स्तंभों शिकायत ट्रैकिंग, समयबद्ध निवारण, नागरिक फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा कुशल निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक दर्ज शिकायत को 12 अंकों का विशिष्ट टोकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता हर चरण में अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। नागरिकों की सुविधा ▶▶ शेष पेज 11 पर

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम है, इसमें 1076 डायल कॉल, पोर्टल, वाट्सअप पेज, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शामिल है। इसमें जो आवेदन लिख नहीं पाते उनके लिए कॉल बैक करने का अनुरोध का भी विकल्प है, जिससे उनको कॉल बैक कर उनके आवेदन को दर्ज किया जाएगा।

देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनेगा रायपुर में, अंतिम चरण में टेंडर प्रक्रिया

पीपीपी एप्रेजल कमेटी से मंजूरी, डेवलपर तय होने के बाद बनेगी ड्राइंग डिजाइन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ में जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग को नई पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुंबई, सूरत और कोलकाता के बाद यह देश का चौथा जेम एंड ज्वेलरी पार्क होगा। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की पहल पर राजधानी रायपुर के पंडरी क्षेत्र में लगभग 9.616 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क विकसित किया जाएगा।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पीपीपी एप्रेजल कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। 30 वर्ष की लीज अवधि (नवीनीकरण सहित कुल 90 वर्ष) और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह पार्क प्रदेश में निवेश, रोजगार और उद्योग विकास के नए अवसर सृजित करेगा। प्रस्तावित जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क को केवल सराफा कारोबार का केंद्र ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पहले 'वेडिंग डेस्टिनेशन मॉल' के रूप में भी विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत लगभग 3.5 लाख वर्गफुट क्षेत्र विशेष रूप से जेम्स एवं ज्वेलरी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, आयातकों-निर्यातकों और वर्कशॉप उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित रहेगा। चतुर्थ तल पर सम्मेलन, व्यापार बैठक एवं प्रदर्शनी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहां आधुनिक दुकानें, थोक कार्यालय, सुरक्षित वर्कशॉप, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी सुविधाओं के साथ केंद्रीयकृत सुरक्षा और अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना में बीआईएस एवं हॉलमार्किंग केंद्र, सामान्य सुविधा केंद्र, बैंकिंग सुविधा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संस्थान तथा स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

'वेडिंग डेस्टिनेशन मॉल' का भी विकास

वहीं, शेष उपलब्ध एफएआर क्षेत्र में डेवलपर को वाणिज्यिक और मनोरंजन गतिविधियों के विकास की स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत परिधान, फूल-सज्जा, फोटोग्राफी, विवाह आयोजन और अन्य विवाह-संबंधित कारोबारों के लिए स्थान विकसित किए जाएंगे, जिससे यह परिसर एक समेकित 'वेडिंग डेस्टिनेशन मॉल' के रूप में उभर सकेगा।

रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस परियोजना राज्य में व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ-साथ रायपुर को जेम्स एवं ज्वेलरी कारोबार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पार्क की स्थापना से रायपुर एवं आसपास के राज्यों के ग्राहकों को विश्वस्तरीय जेम्स एवं ज्वेलरी खरीदारी का अनुभव प्राप्त होगा। स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

टेंडर की प्रक्रिया जारी

सीएसआईडीसी द्वारा आरपीएफ 24 अप्रैल को जारी किया गया। बोलियाँ 15 मई तक प्राप्त की गईं। उसी दिन तकनीकी बोलियाँ विधिवत खोली गईं। वर्तमान में बोली मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त बोलियों का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया प्रगति पर है। जो बोलीदाता तकनीकी चरण में अर्ह पाये जाएंगे उन्हें वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि से सूचित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया में बोली का आधार जेम एंड ज्वेलरी पार्क के लिए अधिकतम लीज प्रीमियम होगा। शीघ्र ही सफल बोलीदाता का चयन कर परियोजना कार्यान्वयन के लिए करार किया जाएगा।

सराफा उद्योग के लिए ऐतिहासिक : राजीव अग्रवाल

सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि 2015 से यह परियोजना अटकी हुई थी। छत्तीसगढ़ के सराफा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। कौशल विकास, बीआईएस प्रमाणन एवं हॉलमार्किंग सुविधाओं के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि होगी। पीपीसी मोड पर विकास के कारण राज्य शासन पर न्यूनतम वित्तीय भार पड़ेगा।

खबर संक्षेप

तेलीबांधा तालाब के पास तेलीन दाई की मूर्ति लगाने की मांग

रायपुर। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नगर निगम स्थित कक्ष में सोमवार को रायपुर शहर जिला साहू संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर तेलीबांधा तालाब में माता तेलीन दाई की मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि रायपुर शहर का ऐतिहासिक तेलीबांधा तालाब साहू तेली समाज की प्राचीन धरोहर और सांस्कृतिक पहचान है। यह स्थान न केवल जनमानस के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी गहरा जुड़ाव रखता है। समाज की अस्मिता और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेलीबांधा तालाब के समीप माता तेलीन दाई की एक भव्य मूर्ति स्थापित की जाए। नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से दिलीप कुमार साहू, कार्यवाहक अध्यक्ष सुंदरलाल साहू सहित शहर जिला साहू संघ के सदस्य उपस्थित रहे।

रामाराम जलाशय योजना के लिए 1.16 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा सुकमा जिले के विकासखण्ड सुकमा के अंतर्गत रामाराम जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1 करोड़ 16 लाख 6 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह पहल सुकमा क्षेत्र में कृषि विकास को गति देने और स्थानीय किसानों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना के प्रस्तावित कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर क्षेत्र के स्थानीय किसानों को 69 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी। जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना के कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराने के लिए मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग (जगदलपुर) को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। योजना के पूर्ण होने के बाद, रूपांकित सिंचाई क्षमता में आ रही कमी पूरी होगी और पूरे क्षेत्र को पर्याप्त सिंचाई का लाभ मिलेगा।

नील हरित शैवाल से सुधर रही मिट्टी की सेहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान अब जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में प्रदेश के कई किसान मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन लागत कम करने और दीर्घकालीन कृषि लाभ सुनिश्चित करने के लिए जैविक विकल्पों की ओर अग्रसर हैं। नील हरित शैवाल (ब्लू-ग्रीन एल्गी) का उपयोग भी ऐसी ही एक प्रभावी तकनीक के रूप में उभर रहा है, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति कर उसकी उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। प्रदेश में कई प्रगतिशील किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक खेती को अपनाते हुए जैविक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। सरगुजा जिले के किसान श्री धनेश्वर प्रसाद ने भी कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपनी खेती में नील हरित शैवाल आधारित जैविक पद्धति को अपनाया है। मिट्टी परीक्षण में नाइट्रोजन की कमी पाए जाने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर नील हरित शैवाल उत्पादन की पहल की, जिससे खेतों को प्राकृतिक पोषण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

70- से 80 प्रतिशत राशि मिलेगी अनुदान के रूप में

पीएम ई-ड्राइव योजना-छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क की तैयारी, मांगी जमीन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों और जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं से ऐसे उपयुक्त स्थलों की जानकारी मांगी है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा सकें। यह पहल केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत की जा रही है। इस योजना के लिए 70 से 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का अनुमान है कि नगर निगम क्षेत्रों में दोपहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगभग 25 से 30 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए स्थानीय निकायों को संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों बढ़ रही है चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत

देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता रही है। जानकारों का मानना है कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार हुए बिना इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाना मुश्किल होगा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है, जिसके तहत सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 800 वर्गफीट भूमि जरूरी

किन स्थानों को मिलेगी प्राथमिकता

विभागीय निर्देशों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाने हैं जहां वाहन खड़े करने की पर्याप्त क्षमता हो और आम लोगों की पहुंच आसान हो। पार्किंग स्थल, बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र, अस्पताल परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही सरकारी या नगर निगम स्वामित्व वाली भूमि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। स्थल चयन के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वहां बिजली कनेक्शन उपलब्ध हो या निकट भविष्य में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक प्रस्तावित स्थल का अक्षांश-देशांतर और कम से कम दो फोटोग्राफ भी भेजने होंगे।

चार्जिंग स्टेशन के लिए क्या होंगे मानक?

दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन के लिए लगभग 800 वर्गफुट भूमि उपलब्ध होना आवश्यक होगा। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन की न्यूनतम कुल क्षमता 144 किलोवाट रखने का प्रस्ताव है, ताकि एक साथ कई वाहनों को चार्ज किया जा सके। स्थल चयन से पहले उसकी व्यवहार्यता(फिजिबीलिटी) और उपयोगिता का परीक्षण भी किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक निवेश का अधिकतम लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार देगी भारी अनुदान

योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय सहायता है। विभागीय पत्र के अनुसार 'बी' श्रेणी के नगर निगम क्षेत्रों में स्थापित होने वाले चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत अधोसंरचना (अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर) की लागत का 80 प्रतिशत और चार्जिंग मशीनों एवं उपकरणों की लागत का 70 प्रतिशत तक अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। शेष राशि की व्यवस्था संबंधित नगर निगमों को करनी होगी। इसके लिए उन्हें जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर उपलब्ध वित्तीय स्रोतों से आवश्यक धन जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के लिए क्या मायने

छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार शुरुआती विस्तार के दौर में है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा जैसे शहरों में ई-स्कूटर और ई-कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। सरकार के इस कदम को राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। फिलहाल नगर निगमों और नगर पालिकाओं से उपयुक्त स्थलों की पहचान कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, जिसके बाद योजना के क्रियान्वयन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी।

खेत बचाओ अभियान किसान मारो अभियान साबित हो रहा : धनेंद्र

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे "खेत बचाओ अभियान" की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह अभियान वास्तव में खेत बचाने का नहीं, बल्कि किसानों को संकट में डालने और उनकी समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खरीफ फसल का सीजन शुरू हो चुका है और किसान खेती-किसानी के कार्यों में जुट गए हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रदेश भर में किसान सोसायटियों और खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार अब किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने की सलाह दे रही है, जो पूरी तरह से अव्यावहारिक और किसान विरोधी है।

किसानों के बजाय व्यापारियों को खाद

धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की सहकारी समितियों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के बजाय बड़े पैमाने पर निजी व्यापारियों को खाद की आपूर्ति कर रही है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का दायित्व किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नए-नए अभियान चला रही है।

खाद न मिलने से किसान निराश

श्री साहू ने कहा कि एक ओर सरकार ने खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, दूसरी ओर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। किसानों को ना ही सोसाइटी में और ना हीं बाजार में खाद मिल रहा है। ऐसे समय में किसानों को उर्वरकों का उपयोग कम करने की सलाह देना उनकी समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि उन्हें बर्बाद करना है। इससे किसान वर्ग में भारी नाराजगी और निराशा का माहौल है। श्री साहू ने कहा है कि भाजपा सरकार बहानेबाजी छोड़कर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाए तथा उपलब्ध समस्त खाद को निजी व्यापारियों के बजाय सहकारी समितियों और सोसायटियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिससे खरीफ सीजन की खेती प्रभावित न हो और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

भाजपा बोली-जनता की लिक्विडिटी छीनकर गोवा के होटलों में निवेश कर रही थी कांग्रेस

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय ने शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए छठवें पूरक आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा, इसमें कांग्रेस सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के नए और चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस महाघोटाले के कारण आज छत्तीसगढ़ में नकदी और मुद्रा तरलता (लिक्विडिटी) का भारी अभाव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का हक मारकर यहां का पैसा दूसरे राज्यों में अवैध रूप से निवेश किया गया, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई है।

श्री पाण्डेय ने कहा, शराब घोटाले की काली कमाई का लगभग 110 करोड़ रुपया कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के माध्यम से नॉर्थ गोवा के 'होटल वेस्टिन' को खरीदने में लगाया गया है। ईडी ने इसके पुख्ता प्रमाण चार्जशीट में जोड़े हैं। इस पूरे घोटाले में अब तक लगभग 89 आरोपियों को नामजद किया गया है, और अपराधियों से कुल 1,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को ईडी द्वारा फ्रीज या सीज किया जा चुका है। ताजा चार्जशीट में ही 200 करोड़ रुपए की नई बेनामी और अवैध संपत्ति का पता चला है। श्री पाण्डेय ने मांग की है कि बेनामी ट्रांजेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इस भयावह खेल पर कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्री पाण्डेय ने कहा, छत्तीसगढ़ की यह लूट अकेले नहीं हुई। इसमें राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े व्यवसायियों की तिकड़ी का एक मजबूत सिंडिकेट सक्रिय था। इस सिंडिकेट के कई तत्कालीन मंत्री और अधिकारी आज भी जेलों में बंद हैं। श्री पाण्डेय ने सवाल उठाया, इतने बड़े घोटाले और गंभीर आरोपों के बाद भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। कांग्रेस के पास केंद्रीय एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाने के अलावा कोई सीधा स्पष्टीकरण नहीं है।

बोरियाखुर्द में आरसीसी नाली निर्माण का कार्य जल्द होगा शुरू

रायपुर विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी किया

- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना में 1800 आवासों का किया था निर्माण

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

रायपुर विकास प्राधिकरण की बोरियाखुर्द स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के रहवासियों की सालों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। सालों पुरानी जर्जर नाली की जगह नई निकास नाली का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है।

दरअसल, वर्ष 2009 में निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत करीबन 1800 आवासों का निर्माण कराया गया था। उस समय की बनाई गई ज्यादातर नालियां जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय रहवासियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा बोरियाखुर्द में नालियों के पुनर्निमाण की मांग लगातार उठाई जा रही थी।

अब प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू ने इसे संज्ञान में लिया है। रायपुर विकास प्राधिकरण अपने स्वयं के व्यय से नाली निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्राधिकरण ने निविदा जारी कर दी है।

पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे

नगरीय निकायों में 30 जून तक होंगे स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

मेहनतकश स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के छह साल पूरे होने के मौके पर नगरीय निकायों में 30 जून तक लोक कल्याण मेलों के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में जिला स्तरीय स्वनिधि महोत्सवों का भी आयोजन किया जाएगा।

राज्य शासन ने स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेलों के आयोजन के लिए सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से जारी परिपत्र में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स), शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लाभों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण ही नहीं, सुरक्षा और सम्मान भी : साव

होंगे स्वनिधि महोत्सव

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में विशेष रूप से स्वनिधि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में बैंकों के प्रतिनिधि छोटे व्यापारियों को ऋण स्वीकृति, वितरण, यूपीआई पंजीयन, क्यू-आर कोड सुविधा और डिजिटल भुगतान संबंधी सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराएंगे। स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

साव ने कही ये बात

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से बैंकों को लंबित ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से नए आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को समय पर पूंजी मिलती है, तो केवल उसका व्यवसाय ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और जीवन की उम्मीद भी मजबूत होती है।

भ्रम फैलाकर आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस : कश्यप

कश्यप ने कहा- बैज का बयान कांग्रेस की आदिवासी-विरोधी राजनीति को छिपाने का प्रयास

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- भाजपा सरकार आदिवासियों के मौलिक और नैसर्गिक अधिकार से वंचित करने का षड़यंत्र : बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार पर से आदिवासी समाज का भरोसा उठ गया है। भाजपा सरकार आदिवासी समाज को प्रताड़ित कर रही है। राज्य के आदिवासी, सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं।

वन मंत्री केदार कश्यप ने श्री बैज के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस को आदिवासी हितों पर सवाल उठाने से पहले अपना राजनीतिक इतिहास देखना चाहिए। जिन कानूनों और अधिकारों की आज कांग्रेस बात कर रही है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा स्वयं कांग्रेस की नीयत और नीतियां रही हैं। वनमंत्री कश्यप ने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक समझकर राजनीति की, लेकिन उन्हें उनके अधिकारों, संसाधनों और विकास से जोड़ने का ईमानदार प्रयास कभी नहीं किया। आज जब छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, वनाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आदिवासी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तब कांग्रेस इसे भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है।

कांग्रेस का जनाधार आदिवासी क्षेत्र में सिकुड़ रहा

उन्होंने कहा कि दीपक बैज और कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद पेसा और वनाधिकार कानून का लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच सका। आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के अवसरों का अभाव किसकी देन था, यह देश अच्छी तरह जानता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का वास्तविक दर्द आदिवासी अधिकार नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में उसका लगातार सिकुड़ता जनाधार है।

भाजपा आदिवासियों को वनवासी बताकर उनके अधिकार छीनना चाह रही : बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, भाजपा के राज सुनियोजित तरीके से आदिवासियों पर उनकी संस्कृति पर हमले हो रहे। भाजपा सरकार जल, जंगल, जमीन पर से आदिवासियों के मौलिक और नैसर्गिक अधिकार से वंचित करने का षड़यंत्र कर रही है। पेसा कानून को कमजोर किया जा रहा है, केंद्र ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन कर दिया है। आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिशों का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा,भाजपा आदिवासियों को वनवासी बताकर उनका मूल संस्कृति से उनको तोड़ने का काम कर रही है। आरएसएस और भाजपा आदिवासियों को उनके जंगल पर से प्राकृतिक अधिकार और पहचान छीनना चाहते है। आदिवासी समाज को वनवासी बताना भाजपा का षड़यंत्र है। आदिवासियों के उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़े विषयों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आदिवासी अस्मिता और सम्मान का मुद्दा है।

खबर संक्षेप

पीएससी सेंटर में रहेगी ओआरएस की व्यवस्था

रायपुर। सीजी पीएससी मेंस 6 से 9 जून तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसकी संपूर्ण तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में बैठक ली। कलेक्टर ने कहा, सभी केन्द्राध्यक्ष परीक्षार्थियों की सुविधा पर ध्यान दें। स केन्द्रों में मूलभूत सुविधा, बिजली, पेयजल इत्यादि सुनिश्चित करें। साथ ही गर्मी को देखते हुए, कूलर, ओआरएस और ठंडे पेयजल की भी व्यवस्था करें। सभी केन्द्राध्यक्ष परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का होना सुनिष्चित करें। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीजीडीएफ का भी होगा विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन में आगामी संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत सितंबर माह के बाद वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी सहित सभी पदों पर परिवर्तन किए जाने की संभावना है। योग्य उम्मेदवारों का चयन छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन की प्रशासनिक बॉडी के द्वारा किया जाएगा। सीजीडीएफ के प्रदेश अध्यक्ष डा. हीरा सिंह लोधी ने बताया कि संगठन के प्रति समर्पित, सक्रिय और योग्य सदस्य इन पदों के लिए अपनी रुचि और दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में फेडरेशन का विस्तार किया जाएगा। इससेसंगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकेगा और डॉक्टरों की समस्याओं एवं हितों की आवाज़ को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

निजी फार्मेसी कॉलेजों में बिना परीक्षा प्रवेश का दावा अवैधः आईपीए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र-हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध इण्डियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रांच ने राज्य के कुछ निजी शिक्षण संस्थानों और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे अवैध प्रवेश विज्ञापनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने तकनीकी शिक्षा संचालनालय नया रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराकर दोषी संस्थानों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव फार्मासिस्ट राहुल वर्मा ने बताया कि जगदलपुर और भिलाई के संस्थानों द्वारा बिना परीक्षा सीधे प्रवेश का भ्रम फैलाया जा रहा है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी निजी संस्थान के बहकावे में न आएं। फार्मेसी में प्रवेश केवल और केवल शासकीय काउंसलिंग और पीपीएचटी परीक्षा के माध्यम से ही लें, ताकि आपका भविष्य और समाज का स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहें।

रेलवे स्टेशन-बस टर्मिनल में लगी नशामुक्ति प्रदर्शनी

रायपुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक दिन के लिए नशामुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बस टर्मिनल भाठागांव में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर मीनल चौबे और रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने किया। साथ में ब्रह्माकुमारी भावना, ब्रह्माकुमारी चंद्रकला, ब्रह्माकुमारी निधि और ब्रह्माकुमारी पूर्णिमा दीदी उपस्थित थीं। इसी तरह रेलवे स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौड़, रेल मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) राकेश सिंह और रायपुर सेवाकेंद्र की संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी ने किया।

कुशल मार्गदर्शन, योजना एवं सहयोग से संपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

अंबुजा विद्यापीठ में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अंबुजा विद्यापीठ, रवान में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना तथा उनमें राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक सद्भाव और भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना था।

विद्यार्थियों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अभिवादन प्रस्तुत कर भारत की भाषाई विविधता का सुंदर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, भोजपुरी एवं बंगाली भाषाओं से संबंधित संगीत एवं प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को आकर्षक और जीवंत बना दिया।

स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित प्रस्तुतियों में विद्यार्थियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस, नेतृत्व एवं देशभक्ति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य और बलिदान का मंचन कर दर्शकों को गौरवान्वित किया गया।

पंजाबी संगीत की धुनों पर आधारित मार्केट सीन ने विद्यार्थियों की अभिनय प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त कहानी वाचन सत्र में छात्र श्याम सुंदर ने तमिल भाषा से संबंधित तथा छात्र आकर्ष ने भोजपुरी भाषा से संबंधित रोचक कहानियाँ प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देश रंगीला गीत पर प्रस्तुत रंगारंग नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस प्रस्तुति ने भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं राष्ट्रीय एकता का सुंदर संदेश दिया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस. के. पाण्डेय ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में भारतीय भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान एवं रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में कार्यक्रम समन्वयक उषा पाखोड़े एवं विद्यालय की काउंसलर सुश्री वैदेही येवलेकर का विशेष योगदान रहा। उनके कुशल मार्गदर्शन, योजना एवं सहयोग से संपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस अवसर पर विद्यालय के उप-प्राचार्य पद्माकर मिश्रा, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता की सराहना की।

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। भारतीय भाषा समर कैंप ने विद्यार्थियों को भारत की विविध भाषाओं, संस्कृतियों एवं परंपराओं को समझने और उनके प्रति सम्मान विकसित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया। यह आयोजन /"एक भारत श्रेष्ठ भारत/" की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल सिद्ध हुआ।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे एवं भाजपा नेत्री और रायपुर जिला पंचायत सभापति सरोज चंद्रवंशी भी शामिल थीं। धरसीवा थाना अंतर्गत सिलियारी चौकी क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक श्वेता सिंह को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि घटना 18 अप्रैल की बताई जा रही है, किंतु मामले में समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। इस दौरान मांग की गई कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषी आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सिलियारी चौकी प्रभारी जितेंद्र दुबे की भूमिका की जांच कर उन्हें तत्काल निलंबित किए जाने की मांग भी की गई।

जनप्रतिनिधि को चौकी प्रभारी की धमकी निंदनीयः बंजारे

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मामले को उठाए जाने से बौखलाकर सिलियारी चौकी प्रभारी जितेंद्र दुबे ने जिला पंचायत सभापति एवं भाजपा नेत्री सरोज चंद्रवंशी के निवास पहुंचकर उन्हें धमकी दी। बताया गया कि चौकी प्रभारी ने सभापति सरोज चंद्रवंसी के किसी पुराने मामलों का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी, जो एक जनप्रतिनिधि को डराने-धमकाने का प्रयास है।

चौकी प्रभारी को निलंबित करने की मांग

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे एवं जिला पंचायत सभापति सरोज चंद्रवंशी ने पुलिस अधीक्षक श्वेता सिन्हा से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। चौकी प्रभारी जितेंद्र दुबे की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है।

जिले की पंचायतों में ग्रामसभा 5 जून को

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलाईगढ़

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य को दिए गए निर्देशानुसार, राज्य के समस्त ग्राम पंचायतो में 5 जून को विशेष ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। इसमें कई बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जानी है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में चर्चा कर संकल्प पारित किया जायेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सम्बन्ध में मान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुवादित प्रति का वाचन कर जानकारी देना। ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है तथा वीडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष यह आयोजन स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान के मुख्य घटक के रूप में मनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता हासिल करने के लिए जन भागीदारी को मजबूत करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विशेष ध्यान समुदाय के नेतृत्व में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जमीनी स्तर पर सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह प्राथमिकताएं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, विशेषकर 'स्वच्छ और हरित ग्राम' थीम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

■ स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण पर होंगे विविध कार्यक्रम

विशेष ग्राम सभा का मुख्य विषय, ग्राम सभा के दौरान जिन बिंदुओं पर व्यापक चर्चा, जागरूकता और संवेदीकरण किया जाएगा उनमें ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन : परिवारों के स्तर पर कचरे को 4 श्रेणियों (गीला, सूखा, सेनेटरी और हानिकारक) में अलग-अलग करने के लिए अनिवार्य परिवर्तन पर चर्चा। घरेलू और संस्थागत स्तर पर जैविक कचरे से खाद बनाने को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से कम करने के लिए जन-आंदोलन चलाना है। जल संरक्षण अंतर्गत स्थानीय जल निकायों (तालाब, टैंक आदि) को कचरा डंपिंग से बचाना, सामुदायिक निगरानी व्यवस्था करना और जन-भागीदारी के माध्यम से जल निकायों की गाद निकालना। इसके साथ ही गाँव के स्तर पर जल संसाधन मानचित्रण करना। स्वच्छता एवं स्वच्छता नियम ग्रामीण स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति जागरूकता फैलाना, जन-भागीदारी एवं समावेशी अधिदेश, ग्राम सभा में समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, स्वच्छाग्रहियों, स्वच्छता कर्मियों, महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्थानीय जागरूकता गतिविधियां में ग्राम सभा के साथ-साथ सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी, जिसमें सामूहिक पर्यावरण शपथ ग्रहण समारोह, नुक्कड़ नाटक और रैलियों का आयोजन, सामुदायिक श्रमदान के माध्यम से गाँव के सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और साझा मैदानों की सफाई एवं पौधारोपण अभियान, लाउडस्पीकर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा दीवारों पर कचरा पृथक्कीकरण से संबंधित संदेश व पेंटिंग बनाना आदि शामिल है।

मंत्री टंकराम ने जनसमस्याओं के निराकरण के लिए दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति की

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

क्षेत्र में विकास कार्यों की सतत निगरानी, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान तथा प्रशासनिक समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री एवं बलौदाबाजार विधायक टंकराम वर्मा ने दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। मंत्री वर्मा ने जनपद पंचायत बलौदाबाजार की नियमित बैठकों एवं विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भाजपा नेत्री सुनीता वर्मा को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया है। वहीं जिले में विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं तथा आम उपभोक्ताओं की विद्युत शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कपिल कश्यप को विद्युत विभाग हेतु अपना आधिकारिक प्रतिनिधि बनाया है।

■ मंत्री ने नियुक्ति की जानकारी कलेक्टर को दी

इस संबंध में कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को आधिकारिक पत्र जारी कर अवगत कराया गया है। आदेश के अनुसार संबंधित विभागों की बैठकों एवं समीक्षा कार्यक्रमों की सूचना अब मंत्री के साथ-साथ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठा सकें और समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकें। सुनीता वर्मा जनपद पंचायत बलौदाबाजार की जनपद सदस्य रहने के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति का दायित्व भी निभा चुकी हैं। उनके अनुभव का लाभ क्षेत्र के विकास एवं जनहितकारी कार्यों में मिलने की उम्मीद है। वहीं कपिल कश्यप जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, वोल्टेज संबंधी समस्याओं के समाधान, खराब एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों के शीघ्र प्रतिस्थापन तथा नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे। वे विभागीय समीक्षा बैठकों में मंत्री की ओर से उपस्थित होकर आम नागरिकों, किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से रखेंगे। मंत्री टंकराम वर्मा की इस पहल को जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे विकास कार्यों को गति मिलने के साथ-साथ आम जनता की समस्याओं के निराकरण में भी तेजी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नियुक्ति पर सुनीता वर्मा एवं कपिल कश्यप ने मंत्री टंकराम वर्मा के प्रति आभार जताया।

प्रो.शाहिद अली की पुनः नियुक्ति को लेकर जारी है विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, लेकिन विवि ने दे दी एंट्री! भड़के छात्रों का बवाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

पत्रकारिता विवि में मंगलवार दोपहर जमकर हंगामा हुआ। यहां एबीवीपी ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, कुलपति कार्यालय का घेराव किया। एबीवीपी ने विवि में प्रशासनिक अनियमितताओं, छात्र विरोधी नीतियों एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभाविप ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेवा समाप्ति की कार्यवाही के बावजूद पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली को बिना किसी वैधानिक आदेश के पुनः विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है। साथ ही वर्ष 2019 में डॉ. शैलेंद्र खंडेलवाल की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाते हुए इसकी जांच की मांग की गई। परिसर में लगभग 7 करोड़ की लागत से निर्मित नए ऑडिटोरियम की हालत जर-जर हो चुकी है। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए एबीवीपी ने इसकी भी तकनीकी जांच की मांग की है।

बदले जा रहे पाठ्यक्रम के नाम

प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम के नाम परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न भ्रम, परीक्षा अवधि में लगातार विद्युत बाधित होने, छात्रावास में दूषित पेयजल, मेस की निम्न गुणवत्ता, खेल सुविधाओं के अभाव, बस परिवहन की अव्यवस्था एवं विद्यार्थियों के लिए स्टूडियो सुविधाओं के उपयोग न होने जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री अनंत सोनी ने कहा, सेवा समाप्ति के आदेश के बाद भी किसी व्यक्ति को विवि में कार्य करने की अनुमति प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

इंडक्शन इस्तेमाल की अनुमति

छात्रावासों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, निर्धारित स्थान पर इंडक्शन उपयोग की अनुमति तथा करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित स्टूडियो को विद्यार्थियों के लिए तत्काल संचालित करने की मांग भी की गई। अभाविप के महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा, करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित ऑडिटोरियम उद्घाटन से पूर्व ही क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। घंटों चले प्रदर्शन एवं घेराव के पश्चात कुलसचिव ने विद्यार्थियों से जुड़ी अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

पेज 9 के शेष

तिरुपति रक्सौल के...

है।वैसे भी भाटापारा में पिछले 7 वर्षों से एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं मिला है,और अभी वर्तमान में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ट्रेनों का ठहराव ना होना भाटापारा की भोली भाली जनता के विश्वास को तोड़ने वाली बात हो रही है। तिरुपति रक्सौल एक्सप्रेस के चालू होने और भाटापारा में उसका ठहराव ना मिलने से अब भाटापारा स्टेशन पर नहीं रुकने वाली ट्रेनों की संख्या 50 को पार करते हुए 52 तक पहुंच गई है। क्षेत्र की नाराज जनता का कहना है कि रायपुर बिलासपुर के मध्य 112 किमी की दूरी के लिए उक्त ट्रेन लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय ले रही है,ऐसे में उक्त ट्रेन का 2 मिनट स्टॉपेज यहां देने से रायपुर बिलासपुर की समय सारणी में कोई बदलाव भी नहीं होगा,अतएव 17433/17434तिरुपति रक्सौल एक्सप्रेस का भाटापारा स्टॉपेज शीघ्र स्वीकृत किया जाए।

केंद्र सरकार की उपलब्धियों...

करते हुए कार्यशाला के उद्देश्य एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विगत 12 वर्षों में विकास, सुशासन, जनकल्याण, आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। उपस्थित कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया पार्टी के रीती नीति के तहत कार्य करें तथा प्रदेश और जिला से प्रेषित कार्यक्रमों को मंडल स्तर पर संपादित करने कि बात कही। कार्यशाला में जिला प्रभारी एवं जिला महामंत्री विजय यादव ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं, उपलब्धियों एवं संगठन द्वारा चलाए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 23 जून तक विभिन्न जनसंपर्क एवं जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवधि में बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक विकसित भारत संकल्प, चौपाल, लाभार्थी संपर्क अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, प्रेस वार्ता, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, युवा एवं महिला सम्मेलन सहित अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक घर तक पहुँचाने के लिए पूरी सक्रियता एवं समर्पण के साथ कार्य करें। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु मंडल स्तर पर व्यापक तैयारी एवं समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन...

हेतु शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 1076 हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नागरिकों की और अधिक सुविधा हेतु सीएम हेल्पलाइन 1076 मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण में पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, स्थिति जांचने, फीडबैक देने की प्रक्रिया, अधिकारियों को लॉगिन प्रक्रिया, प्रोफाइल अपडेट, डैशबोर्ड संचालन, लंबित शिकायतों की समीक्षा, समाधान विकल्प चयन एवं प्रतिवेदन (एटीआर) अपलोड के बारे में विस्तृत से बताया गया। प्रशिक्षकों द्वारा शिकायत श्रेणी (कंप्लेंट कैटेगरी) की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया। प्रत्येक श्रेणी के लिए विभाग द्वारा एल-1 से एल-4 तक के अधिकारियों की पदनामवार मैपिंग की गई है। शिकायत निवारण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायत का निराकरण नहीं होने पर शिकायत स्वतः अगले उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी।

बिजनेस साइड

सुयोक्ता मोटर्स ने लॉन्च किया '10 पे 21 का दम' ऑफर

भाटापारा। खेती-किसानी के क्षेत्र में अग्रणी ट्रैक्टर ब्रांड न्यू हॉलैंड के अधिकृत डीलर, सुयोक्ता मोटर्स तरेंगा रोड भाटापारा ने किसानों के लिए एक विशेष लाभकारी योजना 10 पे 21 का दम' की घोषणा की है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यदि कोई ग्राहक मात्र 10,000 की राशि से ट्रैक्टर की बुकिंग कराता है, तो उसे 21,000 की रसीद प्राप्त होगी। इस प्रकार, ग्राहकों को सीधे 11,000 तक का फायदा मिल रहा है। यह ऑफर न्यू हॉलैंड के लोकप्रिय मॉडल 3630 TX Super Plus पर मान्य है। योगेश दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि, कंपनी ने इस ट्रैक्टर में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें अपग्रेडेड FPT इंजन अधिक शक्ति और बेहतर माइलेज के लिए सेंसोमैटिक 24 हाइड्रोलिक लिफ्टिंग जो खेती के उपकरणों को आसानी से नियंत्रित करने के लिए आधुनिक तकनीक है, नया प्लेटफॉर्म जो कि डबल फुटस्टेप्स और हीटगार्ड की सुविधा है, जिससे चालक को लंबी अवधि तक काम करने में आसानी होती है। इच्छुक किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए सुयोक्ता मोटर्स के योगेश दीवान के तरेंगा रोड स्थित शोरूम मे संपर्क कर सकते है स्कीम चालू है।

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130

खबर संक्षेप

बैठक में कांग्रेस ने किया महंगाई का विरोध

भटगांव। मंडल कांग्रेस कमेटी भटगांव का एक संगठनात्मक बैठक केशवानी धर्मशाला में आयोजित किया गया। उक्त बैठक में भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार के द्वारा लगातार महंगाई में वृद्धि कर आम जनता को त्रस्त कर दिया है, जिसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।मंडल कांग्रेस कमेटी के बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी भूपेंद्र विक्रांत साहू, नेमीचंद केसरवानी, रामसाय बघेल, कमलेश कुर्रे, ग़ुलाम मृमतजा खान, प्रवेश दुबे ने संबोधित किया सभी वक्ताओं ने भाजपा के केंद्र एवं राज्य सरकार को जमकर घेरा सभी वक्ताओं ने इस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया उक्त बैठक में प्राप्त विभिन्न प्रस्ताव के संबंध में बताते हुए मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामानंद हिरवानी ने बताया कि वर्तमान में कृषि कार्य आरंभ हो चुका हैं और किसानों को सही समय पर खाद्य और बीज सही दाम में उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस विषय पर शीघ्र ही किसान हित में आंदोलन किया जाएगा उक्त बैठक में किशोर निराला, परमेश्व दयाल कोसले, दिलहरन साहू, फिरितलाल खटकर, अप्पू नवरंग, चंद्र शेखर हिरवानी, राजकुमार जायसवाल, त्रिलोक साहू, भागीरथी चंद्रा, जलील खान, शेख मुजीब, रघुनाथ साहू, रामकुमार साहू, नवद राम हिरवानी, बुधराम यादव, जावेद खान, मनोज कुमार टंडन, पीतांबर साहू, रमेश कुमार यादव, लक्ष्मण जोलहे, राहुल साहू, गुलाम जावेद खान, अनिल जायसवाल, दिलीप कुमार यादव आदि उपस्थित थे।

निर्माणाधीन गौधाम का निरीक्षण करने पहुंचे जनप्रतिनिधि

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भाटापारा

छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल एवं महात्यागी रामरूप दास के साथ निर्माणाधीन गौधाम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन करते हुए गौधाम को शीघ्र प्रारंभ करने तथा इसे गौसेवा एवं गौसंरक्षण का एक आदर्श केंद्र बनाने के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई।

निरीक्षण के दौरान गौधाम में उपलब्ध कराई जाने वाली व्यवस्थाओं, गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा इसके प्रभावी संचालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

गौसेवा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति

गौधाम प्रारंभ होने से क्षेत्र में गौसंरक्षण को मिलेगी मजबूती

नगर पालिका परिषद भाटापारा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन गौधाम को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इसे एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं आदर्श गौधाम के रूप में विकसित करना है, जहां गौवंश के संरक्षण, उपचार और देखभाल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि गौधाम प्रारंभ होने से क्षेत्र में गौसंरक्षण को मजबूती मिलेगी तथा सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल ने कहा कि गौसंरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। राज्य शासन गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और गौधामों की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि भाटापारा में निर्माणाधीन गौधाम पूर्ण होने के पश्चात क्षेत्र के निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा तथा गौसेवा के कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। महात्यागी महाराज रामरूप दास ने कहा कि गौमाता भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक परंपरा की आधारशिला हैं।

राजस्व मंत्री टंकराम ने 55 लाख से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात

सुशासन तिहार में लोगों की समस्याओं का मौक़े पर हो रहा समाधान

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार/पलारी

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सुशासन तिहार अंतर्गत बुधवार को ग्राम छेरकापुर में आयोजित समाधान शिविर में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल भी उपस्थित रहे।इस दौरान दौरान मंत्री श्री वर्मा ने क्षेत्र के विकास हेतु कई घोषणाएं कीं जिनमें छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापना के लिए 5 लाख रुपये, छेरकापुर में मुक्तिधाम निर्माण और सीसी रोड के लिए 5-5 लाख रुपये, गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर हेतु 12 लाख रुपये तथा सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपये शामिल हैं।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुशासन त्यौहार का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे पहुँचकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक प्राप्त करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी शिविरों में स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि नागरिकों को मौके पर ही चिकित्सकीय परामर्श मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।उन्होंने कहा कि राज्य शासन का यह प्रयास है कि युवा, गरीब, बच्चे और किसान – समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की तकलीफों का समाधान करना है। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी के तहत राज्य शासन द्वारा इस दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है।

इस दौरान ओमप्रकाश चंद्रवंशी, दुर्गा महेश्वर, महेंद्र मोनू साहू, सनकुमार साहू, कमलेश ध्रुव, मोहन बंजारे, जीएस टंडन, दीनदयाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने "मोर गाँव मोर पानी" अभियान 2.0 की जानकारी देते हुए बताया कि जल संचयन दीदियों और ग्राम पंचायतों के प्रयास से ढाई माह में ढाई लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है।उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जारी "हम होंगे कामयाब 2.0" वेब पोर्टल की भी जानकारी दी, जिसके माध्यम से युवा रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। "हम होंगे कामयाब" अभियान 2.0 के तहत युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। खेल विभाग द्वारा स्पोर्ट्स किट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व कार्ड, डिजिटल किसान किताब वितरित किया गया और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

संलग्नीकरण समाप्त करने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला इकाई सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ में खंड चिकित्सा अधिकारी को शासन के आदेशों के परिपालन में समस्त संलग्नीकरण समाप्त किए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशी कुमार जायसवाल के साथ संघ के जिला पदाधिकारियों की विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में शासन एवं स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप सभी संलग्नीकरणों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने तथा कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यरत कराने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने शासन के आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने पर बल दिया। बैठक में यह भी अपेक्षा व्यक्त की गई कि शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अरुण कुमार बंजारे, जिला उपाध्यक्ष मालिक राम जयसवाल, जिला महामंत्री कृष्ण कुमार रात्रे, जिला सचिव तोषण कुमार साहू एवं अन्य पदाधिकारी कमलेश डडसेना उपस्थित रहे।

समय पर खाद-बीज मिलने से किसानों को मिली राहत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बलौदाबाजार

खेती के लिये समय पर खाद-बीज की व्यवस्था किसानों के लिये बड़ी चुनौती होती है लेकिन जिला प्रशासन की बेहतर व्यवस्था से जिले के किसानों को आवश्यकता अनुसार आसानी से खाद बीज उपलब्ध हो रहा है। ग्राम पाहंदा के बालचंद बांधे का जीवन खेतों की हरियाली और मिट्टी की सोंधी महक के बीच बीतता है। पेशे से एक किसान, बालचंद के लिए खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनका जुनून है। इस साल किसान बालचंद अपनी खुद की जमीन के साथ-साथ जमीन रेगहा और अधिया पर लेकर कुल 25 एकड़ पर खेती करने वाले हैं। 25 एकड़ में धान की खेती के लिये दिन-रात की कड़ी मेहनत, सही योजना और सबसे बढ़कर सही समय पर खाद-बीज की जरूरत थी। समय बीतने के साथ बालचंद के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थीं क्योंकि 25 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बार बालचंद की यह चिंता पल भर में दूर हो गई। शासन, प्रशासन और सहकारी समिति की मुस्तैदी के चलते उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक, बिल्कुल सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म के खाद और बीज मिल गए। जब खेतों को जरूरत पड़ेगी, उस वक्त के लिये पहले से खाद-बीज किसान के पास मौजूद है। इस सुचारू और पारदर्शी व्यवस्था ने बालचंद के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान ला दी। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब शासन-प्रशासन इस तरह किसानों के साथ खड़े है, तो आधी चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। समय पर मिले इस सहयोग से उत्साहित बालचंद अब दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने 25 एकड़ के खेतों को संवारने में जुट गए हैं।

■ अग्रिम उठाव से किसान बालचंद की चिंता हुई दूर

संयंत्र गांवों में टैंकरों के माध्यम से कर रहा पेयजल आपूर्ति

हरिभूमि न्यूज ▶▶| हिरमी रावन

भीषण गर्मी एवं जल संकट की स्थिति को देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी के सीएसआर विभाग द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष पहल की जा रही है। संयंत्र द्वारा प्रभावित गांवों में नियमित रूप से पानी के टैंकर भेजकर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। गर्मी के मौसम में भूजल स्तर में गिरावट एवं जल स्त्रोतों के सूखने से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अल्ट्राटेक सीएसआर विभाग द्वारा समीपवर्ती ग्राम मोहरा, बरडीह, कुथरौद, भिलौनी, अमेरी एवं परसवानी में पानी के टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिससे सैकड़ों ग्रामीण परिवारों को राहत मिल रही है। अल्ट्राटेक सीएसआर विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं सामुदायिक जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता को सुदृढ़ करना तथा जल संकट के स्थायी समाधान को बढ़ावा देना है। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के दौरान टैंकरों के माध्यम से नियमित पेयजल उपलब्ध होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है तथा दैनिक जरूरतों की पूर्ति में सुविधा हो रही है। सीएसआर विभाग ने ग्रामीणों से जल के विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन ही भविष्य में जल संकट से बचाव का प्रभावी उपाय है।

नए राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र

जनसमस्या निवारण शिविर में पहुंचे शिवरतन शर्मा

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भाटापारा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार क्रो भाटापारा विकासखंड के ग्राम पंचायत बिजराडीह में सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किए।

शिवरतन शर्मा ने पात्र ग्रामीणों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के स्वीकृति पत्र, पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र, सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियो क्रो सामग्री का वितरण किया। शिवरतन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा स्पष्ट है, कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो। सुशासन तिहार जनता और सरकार के बीच भरोसे का सेतु है। यह अभियान लगातार 40 दिनों तक चलेगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि गांव के अंतिम व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं चलकर उसके पास आए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, विभिन्न पंचायतों के सरपंचों सहित, एसडीएम, जनपद सीईओ, बी एम ओ, बी ई ओ, एस डी ओ, जैसे अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी, भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।